C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 11, Wednesday, November 30, 2016/Agrahayana 9, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
MEMBERS SWORN	9
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 201	13-18
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 202 to220	19-113
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530	114-573

PAPERS LAID ON THE TABLE 575-583

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 584-585

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 586
27th Report

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT 586
14th and 15th Report

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation

Shri D.V. Sadananda Gowda 586

SUBMISSION BY MEMBERS
Re: Impact of demonetisation 587-598

MATTERS UNDER RULE 377 614-638

(i) Need to regularise the services of Aanganwadi workers as Group 'D' employees and also give them adequate wages and allowances and social security benefits as applicable to Group D employees

Shri Sunil Kumar Singh 615

(ii) Need to check the industrial waste and pollution caused by industrial factories in Ujjain Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Prof. Chintamani Malviya 616

(iii) Need to impress upon Government of Uttar Pradesh to enhance the rate of sugarcane and also ensure payment of arrears of sugarcane by sugar mills to farmers in Uttar Pradesh

Shri Raghav Lakhanpal 617

(iv) Need to open a railway station in Ridhpur at Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ramdas C. Tadas 618

(v) Need to ensure timely payment of pension and gratuity to retired employees of Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, Jharkhand

Shri Ram Tahal Choudhary 619

(vi) Need to accord environmental clearance to Uranium Corporation of India Limited mines at Jaduguda, Jharkhand

Shri Bidyut Baran Mahato 620

(vii) Need to develop necessary mechanism to enable people migrated to other States to exercise their right to vote during elections

Shri Rajendra Agrawal 621

(viii) Need to reintroduce free Monthly Season Ticket to students for rail journey

Shri Chandra Prakash Joshi 622

(ix) Need for development and operation of Vadiya Devli Railway station in Amreli Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Naranbhai Kachhadia 623

(x) Need to enhance the Minimum Statutory Price of Moong Dal (Green Gram) in Nagaur, Merta and Degana in Rajasthan

Shri Hariom Singh Rathore 624

(xi) Need to formulate a fair and transparent system under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to ensure meticulous execution of the scheme

Shri Devendra Singh Bhole 625

(xii) Need to formulate a scheme for development of agriculture-based industry, dairy, horticulture sector and small scale industries in Banswara Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Manshankar Ninama 626

(xiii) Regarding drought situation prevailing in Karnataka

Shri D.K. Suresh 627

(xiv) Need to sanction additional funds for construction of fishing harbours at Arthungal and Thottappally in Alappuzha district, Kerala

Shri K. C. Venugopal 628

(xv) Regarding problems faced by farmers of Tamil Nadu due to demonetisation of currency notes

Shri C. Mahendran 629

(xvi) Need to set up food park and Agri-Export Zone in Theni district of Tamil Nadu

Shri R. Parthipan 630

(xvii) Need to provide medicines to poor at affordable prices

Dr. Ratna De (Nag) 631

(xviii) Regarding timely execution of renovation and conservation of Gadakkhai Heritage Project in Cuttack, Odisha

Shri Bhartruhari Mahtab 632

(xix) Need to enhance the rate of pension under Employees' Pension Scheme, 1995

Shri Prataprao Jadhav 633

(xx) Need to establish a cluster-cum-handloom park at Mangalagiri in Andhra Pradesh

Shri Jayadev Galla 634-635

(xxi) Regarding pending projects under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh

Shrimati Kothapalli Geetha 636

(xxii) Need to address the problems of farmers in the country

Shri Kaushalendra Kumar 637

(xxiii) Need to control Sepsis, a life threatening disease

Shri Prem Das Rai 638

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 640

Member-wise Index to Unstarred Questions 641-646

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 647

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 648-649

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, November 30, 2016/Agrahayana 9, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBERS SWORN

HON. SPEAKER: Item No. 1. Secretary-General.

SECRETARY GENERAL: Shri Partha Pratim Ray.

Shri Partha Pratim Ray (Cooch Behar)	oath	Bengali
Shri Dibyendu Adhikari (Tamluk)	oath	Bengali

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान) मैं आपको याद दिला रहा था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक मिनट रुकिए। मुझे मालूम है। I know it. मेरे पास भी है। मुझे याद है लेकिन उस मामले में मैं कुछ और भी जानकारी ले रही हूं। हमेशा करते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी ऑबिच्युरी नहीं। किस बात की? एडजर्नमेंट?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बोलना चाहते हो? मुझे मालूम है। मेरी बात सुनिए। आपने जो ऑबिच्युरी की बात कही है, मैंने एस.जी. से भी कहा है क्योंकि जो मैं सुन रही हूं, combing is on. वह जानकारी पहले पूरी ले लेते हैं, वह होने दीजिए। ऑबिच्युरी देने में कभी कोई बात नहीं है। पूरी रिपोर्ट आ जाए। I know it. आज आपको क्या हो गया?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम हमेशा ऑबिच्युरी करते हैं। मैंने केवल इतना कहा है कि पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। मुझे मालूम है कि सात जवान शहीद हुए हैं। If combing is on, let it complete and we will.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं होता है। देश के जवानों ने देश की रक्षा में अपनी जान दे दी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऑबिच्युरी के लिए क्या किसी ने मना किया है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : खड़गे जी, यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा के बारे में विवाद का विषय नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

11.06 hours

(At this stage, Shri Mallikarjun kharge, Prof. Saugata Roy, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and some other hon'ble Members then left the House)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बात सभी को स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसमें कोई विवाद का विषय हो ही नहीं सकता। अभी तक हमने हर समय पर ऑबिच्युरी की है।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : देश की रक्षा के बारे में राजनीति करना देश हित में नहीं है।...(व्यवधान) Once we get the full details.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? I do not understand.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not fair. I have only one thing to say that combing is on.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, जो जवान बार्डर पर शहीद हुए हैं, उनके लिए सभी की तरफ से श्रद्धांजलि है।...(व्यवधान) पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि है, भारत सरकार की श्रद्धांजलि है।...(व्यवधान) अभी कोम्बिंग ओपरेशन चल रहा है, उसका पूरा ब्यौरा प्राप्त होने के बाद सदन में ऑबिच्युरी प्रस्ताव रखने वाले हैं।...(व्यवधान) यह कोई विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। यह बहुत दुख की बात है कि ऐसे संवेदनशील मामले को विपक्ष विवाद का विषय बना रहा है।...(व्यवधान) यह कतई ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह कोई पोलिटिकल बात नहीं है। हम हमेशा ऑबिच्युरी करते आए हैं। हर जवान को हमने श्रद्धांजलि दी है। इस बात को इस तरह से सदन में उठाया गया है, यह वास्तव में बहुत दुखद बात है। सबके मन में उनके लिए दुख है।

प्रश्न 201 - डॉ0 वीरेन्द्र कुमार।

11.07 hours

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 201 - डॉ0 वीरेन्द्र कुमार।

(Q.201)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई है। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है और उसमें बताया है कि भारतीय आईटी कम्पनियों ने घरेलू स्तर के साथ-साथ यूएसए में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। नैसकॉम के अनुसार स्थानीय स्तर के साथ-साथ यूएसए में रोजगार सृजन की औसत वृद्धि 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत देखी गई है।

महोदया, अमरीका की आईटी कम्पनियों में भारतीय लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारतीय लोगों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व कई अमेरिकियों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका द्वारा भारतीय आईटी पेशेकरों को रोकने के लिए यूएस वीजा शुल्क में वृद्धि की गई है और उस वृद्धि में कितने आईटी पेशेकरों का अमेरिका जाना बाधित हुआ है? क्या सरकार ने इस दिशा में अमेरिकी प्रशासन से बात करके भारतीय आईटी पेशेकरों को संरक्षण दिलाने की कोई पहल की है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, भारत के आईटी क्षेत्र पर देश को गर्व करना चाहिए। दुनिया के 80 देशों के 200 शहरों में हमारी आईटी कम्पनियां हैं और ग्लोबल टेल का 56 परसेंट भारत के पास है। हमें सदन को यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में वर्ष 2015 में 35 लाख लोगों को इस फील्ड में नौकरी मिली है और वर्ष 2016 में यह बढ़कर 37 लाख संख्या होने वाली है। यह प्रत्यक्ष नियुक्ति है और लगभग एक करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष नौकरियां मिली हैं।

महोदया, मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इसमें 30 प्रतिशत महिलाएं हैं। आईटी क्षेत्र ने हर क्षेत्र में बहुत विस्तार से काम किया है और हमारा इनके प्रति पूरा सहयोग है। 'डिजिटल इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया' के माध्यम से हम इस दिशा में और काम करेंगे। मुझे इस बारे में एक बात और कहनी है कि पिछले एक वर्ष में देश में चालीस मोबाइल मैनुफैक्चरिंग कम्पनियां आई

हैं।...(व्यवधान) उनमें लोगों को नौकरियां मिली हैं। जहां तक माननीय सदस्य का अमेरिका के बारे में प्रश्न है, यह सही है कि एल-वन वीजा, एच-वन वीजा में शुल्क वृद्धि हुई है। इस बारे में सरकार की तरफ से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को उठाया है। हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा उनसे स्ट्रक्चर डायलॉग होता है। अमरीका से हमारे संबंध अच्छे हैं। इस बारे में हम और भी काम करेंगे।...(व्यवधान)

सदन को एक बात और बताना जरूरी है कि भारत की आईटी कम्पनियों ने पिछले तीन-चार वर्षों में दो बिलियन डालर वहां निवेश किए हैं और बीस बिलियन डालर टैक्स दिया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत की आईटी कम्पनियां अमेरिका में अच्छा काम कर रही हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चाहे जिस तरीके से हो, लेकिन हल्ला-गुल्ला नहीं करना है, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। ...(व्यवधान) इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। इस क्षेत्र में आउटसोर्सिंग पर भले ही अधिक खतरे न हों, परंतु भविष्य में भारतीय आई.टी. कंपनियों के समक्ष चुनौतियां आने वाली हैं।...(व्यवधान) दुनिया के कई राष्ट्र, जिनमें चीन, अमरीका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको आदि भारत को इस क्षेत्र में सुनियोजित रुप से चुनौती देने की कोशिशों में लगे हुए हैं।...(व्यवधान)

11.11 hours

(*At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Prof. Saugata Roy, Shri Md. Badruddoza Khan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि सरकार नई तकनीकों को बढ़ावा देकर आई.टी. पेशेवरों को डिजिटल तकनीक और डिवाइस थिंकिंग जैसा प्रशिक्षण देकर विश्व परिदृश्य पर भारतीय आई.टी. पेशेवरों की पहचान को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजना बनायेगी?...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा, अभी तक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को बहुत प्रमोट किया है।...(व्यवधान) नई नीति बनाने के लिए हम सार्वजनिक चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि भारत के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी आगे बढ़ें, जिसमें भारत का बहुत ही विशेष स्थान बन रहा है।...(व्यवधान)

इसके अलावा भारत में आई.टी. सर्विसेज और बढ़ें, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज भारत में स्मार्टफोन्स की संख्या लगभग तीस करोड़ से अधिक है।...(व्यवधान) भारत में पचास करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, आधार कार्ड बहुत फैल रहा है तथा अब जो कैशलैस पेमेन्ट का

नया कार्यक्रम चल रहा है, इसमें नई-नई टैक्नोलोजी के माध्यम से नये-नये प्रयोग होंगे और भारत के लोगों का आई.टी. और अधिक एम्पावरमैन्ट होगा। ...(व्यवधान)

मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कॉमन सर्विस सैंटर हमारे देश में लगभग पौने दो लाख हैं, इन्हें बढ़ाकर हम ढाई लाख करने वाले हैं।...(व्यवधान) इसमें महिलाएं, दलित और बाकी लोग काम करते हैं। उन लोगों ने भी लगभग पांच लाख लोगों को नौकरियां दी हैं।...(व्यवधान) इस तरह से भारत का पूरा आई.टी. इको सिस्टम डिजिटल इंडिया के माध्यम से और आगे बढ़ेगा। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. Go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.12 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.04 hours

The Lok Sabha reassembled at Four Minutes past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Sarvashri Mallikarjun Kharge, Jyotiraditya M. Scindia, K.C. Venugopal, Sudip Bandyopadhyay, Jai Prakash Narayan Yadav, Kodikunnil Suresh, Dharmendra Yadav, Prof. Saugata Roy, Smt. P.K. Sreemathi Teacher, Sarvashri P.K. Biju, Jitendra Chaudhary, Shailesh Kumar *alias* Bulo Mandal, Sarvashri N.K. Premachandran, Adv. Joice George, and Md. Salim on demonetization of Rs. 1000 and Rs. 500 currency notes.

The matter though important does not warrant interruption of business of the day. The matter can be raised through other opportunities. I have, therefore disallowed all the notices of Adjournment Motion.

12.05 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House will now take up Papers to be laid on the Table of the House.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5535/16/16]

(2) (एक) नार्थ इंस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उमियम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ इंस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उमियम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5536/16/16]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2015, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 सा0का0नि0653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 2015, जो 10 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0सा0का0नि0241 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5537/16/16]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5538/16/16]

(दो) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5539/16/16]

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam Speaker, on behalf of Shri Mukhtar Abbas Naqvi, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chandigarh Waqf Council, Chandigarh, for the year 2015-2016.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chandigarh Waqf Council, Chandigarh, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5540/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI M.J. AKBAR): Madam, on behalf of General (Retd.) V.K. Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(3) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5541/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5542/16/16]

(2) (i) Review by the Government of the working of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5543/16/16]

(3) (i) Review by the Government of the working of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5544/16/16]

(4) (i) Review by the Government of the working of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5545/16/16]

(5) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5546/16/16]

(6) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5547/16/16]

(7) (i) Review by the Government of the working of the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5548/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5549/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian National Academy of Engineering, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Academy of Engineering, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5550/16/16]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Nano Science and Technology, Mohali, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Nano Science and Technology, Mohali, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5551/16/16]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5552/16/16]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Raman Research Institute, Bangalore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Raman Research Institute, Bangalore, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5553/16/16]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5554/16/16]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5555/16/16]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5556/16/16]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, for the year 2013-2014.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 5557/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Film Development Corporation Limited and the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5558/16/16]

12.07 hours

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL**:** Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

I. `I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 8th August, 2016 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-

"That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee, and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Narendra Budania
2. Shri Hussain Dalwai
3. Shri Ram Taran Dudi
4. Shri B.K. Hariprasad
5. Shri Ahamed Hassan
6. Dr. Vikas Mahatme
7. Shri Vishambhar Prasad Nishad
8. Shri Rajaram
9. Shrimati Vijila Sathyananth
10. Shri Ram Nath Thakur.'

II. I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Tuesday, the 9th August, 2016 adopted the following Motion in regard to the Joint Committee on Offices of Profit:-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do elect one Member of the Rajya Sabha to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by the retirement of Shri K.C.Tyagi from the Rajya Sabha and resolves that

the House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, one Member from amongst the Members of the House to said Joint Committee, to fill the vacancy."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance to the above Motion, Shri Sharad Yadav, Member, Rajya Sabha has been duly elected to the said Committee.

12.07 ¼ hours

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

27th Report

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Madam, I beg to present the Twenty-seventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.07 ½ hours

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
14th and 15th Reports

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदया, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 14वां और 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.07 ¾ hours

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation*

THE MINISTER OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, आई ऐम सॉरी, जो सुबह यहाँ पर ओबिच्युरी रेफरेंस के वक्त हमने उठाया था, वह आपके खिलाफ नहीं था।

माननीय अध्यक्ष : इट्स ओ.के.।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सरकार को जो आपको इनपुट देना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष : ओबिच्युरी स्पीकर की तरफ से था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह इनपुट नहीं देने की वजह से, उनकी गलती की वजह से ऐसी घटना हुई।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इनपुट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के इनपुट का सवाल ही नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यह क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं हूँ।

माननीय अध्यक्ष : ओ.के.।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5559/16/16.

12.08 ½ hours

SUBMISSION BY MEMBERS
Re: Impact of demonetisation

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : यह एक चीज है। दूसरी चीज मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह सदन कम से कम 13 दिन से नहीं चल रहा है। हम भी दुःखी हैं, आप भी दुःखी हैं।...(व्यवधान) सारा देश दुःखी है।...(व्यवधान) आप लोग हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दुःखी हो, यही बहुत बड़ी बात है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सुप्रीम पॉवर है, आप इस सदन की मुखिया हैं और सभी रूल्स को सस्पेंड कर सकती हैं, इतनी अथॉरिटी आपके पास है। रूल 388, रूल 389, इन दोनों रूल्स में इस सदन ने आपको इतनी पॉवर दी है कि आप किसी भी रूल को सस्पेंड कर सकती हैं। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि हमारा जो एडजर्नमेंट मोशन है, रूल 56 के तहत हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन वे लोग वह चर्चा नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी रूल में चर्चा ले लीजिए, जिसमें डिबेट हो जाये और वोटिंग हो।...(व्यवधान) डिबेट हो और वोटिंग हो।...(व्यवधान) मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपको सदन ने रूल 388 और रूल 389 के तहत यह शक्ति दी है कि आप किसी भी रूल को सस्पेंड कर सकती हैं। यह हमने आपके ऊपर छोड़ा है।...(व्यवधान) हम डिबेट के लिए तैयार हैं, हम डिबेट से भागना नहीं चाहते हैं।...(व्यवधान) हम जनता की तकलीफों को सदन के सामने रखना चाहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपके लीडर बोल चुके हैं तो फिर शोर करने से क्या फायदा है, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? गौरव जी, बहुत बड़े हो गये हो। वह आपकी तरफ से सभी बात बोल चुके हैं। मैं सुन रही हूँ।

सुदीप जी आप बोलिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, today morning, we wanted to have an obituary reference for the jawans who have lost their lives.

Our walking out was not an attempt to hurt you. If it has hurt you, we express our regret and we still feel that the Government could not supply you the required information. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह भी गलत बात रिकार्ड में मत लाइए। I said that combing is on. That is why मैंने नहीं किया था। वह मेरा अपना विचार है। उसमें गवर्नमैंट ने जानकारी दी, नहीं दी, ऐसा मत कहें। ऑबिचुरी हमेशा स्पीकर की तरफ से होती है। आप दोनों एक अलग बात प्लीज़ रिकार्ड पर मत लाइए। इसमें गवर्नमैंट का सवाल नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : आपका तो सपोर्ट गवर्नमैंट चाहती है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें गवर्नमैंट का सवाल नहीं है। मैंने केवल इतना ही कहा था कि because combing is on, वहाँ फैमिलीज़ भी हैं, यह सब कुछ चल रहा है। ऑबिचुरी तो हम हमेशा देते आ रहे हैं। उन्होंने भी गलत बात कही, आप भी गलत कह रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : ठीक है, मैं इसमें नहीं जाता। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गवर्नमैंट का इसमें कहीं भी सवाल नहीं है। ऑबिचुरी तो मेरी तरफ से होती है।

…(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : आपने जो दुख व्यक्त किया, वह सही है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सवाल डिफैंड का नहीं है। जो बात है, वह मैं बोल रही हूँ कि what is fact. मैं किसी को डिफैंड नहीं कर रही हूँ। मैं आपको भी डिफैंड करने को तैयार हूँ, मैं पूरे हाऊस की बात कर रही हूँ। I never said that.

…(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Regarding the functioning of the House, it is absolutely correct that we have also given notice for Adjournment Motion under Rule 56 and they are for discussing the issue under Rule 193.

I am of the same opinion that there should be an immediate discussion. You may scrap Rule 56, you may scrap Rule 193 and you have every authority to find out the third way. Why is the Government, in spite of having a brute majority

of more than 300 Members in the House, fighting shy to go for voting? What for? That has to be clarified.

We are for the discussion. We will make our observations, we may shift from Rule 56 for the sake of the country, if necessary, and they should also withdraw their demand for Rule 193 but they should come to a position where you can take a decision. You can endorse any rule which provides for voting.

Discussion with voting is our only demand. You may give your consent and let the discussion start from tomorrow morning. Let us exchange our views and ideas wholeheartedly and in full spirit and then come to a conclusion. We are committed against black money. We are committed to fight black money. We are committed to see that black money holders are sent to prison for their life.

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? सब बात तो हो गई है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये क्या है? यह आपके पीछे जो चल रहा है, क्या यह पद्धति है? I am giving you a warning. यह क्यों दिखाना है? नहीं दिखाना है। You cannot show something like that. I am sorry.

…(व्यवधान)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): When Madam tells you to sit down, please sit down. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: When Madam says not to show something like that, then do not show it. That is also there.

…(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मैडम आप नाराज़ हो रही हैं। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : नाराज़गी की बात तो है ही। पूरा देश नाराज़ है। उसका भी यहाँ पर रिफ्लैक्शन होना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठिये।

श्री मोहम्मद सलीम : मैंने तो अभी तक एक शब्द नहीं कहा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी बोलिये।

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, सब मानते हैं कि यह महत्वपूर्ण फैसला है, इसको नोटबंदी बोलें या डीमॉनेटाइज़ेशन बोलें, यह ऐतिहासिक फैसला है। संसद में सभी लोग चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन किस रूल के तहत चर्चा हो, यह आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। एडजर्नमैंट मोशन हमने दिया। अब 16 तारीख से रोज़ाना हम यहाँ आ रहे हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ...(व्यवधान) कोशिश यह है कि कोई सूरत निकलनी चाहिए और यह सूरत कैसे निकलेगी? ...(व्यवधान) अभी भर्तृहरि महताब जी ने परसों खड़े होकर कहा कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से यह पहल होनी चाहिए थी। जीएसटी लेकर कितना हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार की तरफ से एक पहल की गई। सब लोगों ने कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला हो गया। लोग परेशान हैं। लोक सभा में हम जनप्रतिनिधि के रूप में अगर उस परेशानी को उस शक्ल में नहीं लाएँगे, जैसे माननीय सदस्य '80' दिखा रहे हैं, तो कितनी मौतों के बाद हम यह स्वीकार करेंगे कि कुछ मौतें हुईं? कितनी तकलीफ के बाद हम यह स्वीकार करेंगे कि लोग तकलीफ में हैं। कितनी परेशानियों के बाद हम लोक सभा में जनप्रतिनिधि के नाते यह कह पाएँगे कि हमारे जो कांस्टीट्युएंट्स हैं, वह परेशान हैं। सरकार माने या न माने, यह हकीकत तो है। आप रूल्स के अंदर ही फैसला लेंगी, लेकिन सरकार की जो मंशा है, उसको बेशक आप प्रायॉरिटी देंगी। लेकिन मैं यह कहता हूं कि लोक सभा यह न हो जाए कि वह सरकार की मंशा की अनुयायी हो जाए, तब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वह काला दिन होगा। आपको यह फैसला लेना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि किस तरह से, किस सूरत में जनता की वेदना को यहां व्यक्त करें। मैं जब यह कह रहा हूं, उनके भी बहुत से कांस्टीट्युएंट्स हैं, जिनके मन में वेदना है, वह यहां आनी चाहिए, इसलिए मैं एडजर्नमेंट मोशन के लिए कह रहा हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, आपके पास लोकतंत्र में और संविधान में संसदीय कार्यों को चलाने के लिए असीम शक्ति है, पॉवर है। हम लोगों की डिमांड है कि नियम 56 के तहत बहस हो, लेकिन यदि उसे नहीं माना जाता है तो जिसमें मत विभाजन की गुंजाइश है, उस धारा के मुताबिक बिना विलम्ब किए हुए बहस शुरू होनी चाहिए। मुझे कहना है कि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। हम बहस से नहीं भागते हैं और सत्ता पक्ष को भी बहस से नहीं भागना चाहिए। आपको जनता ने अजेय बहुमत दिया है। अजेय बहुमत वाले आप बहुमत में होंगे, लेकिन मत विभाजन से क्यों भागते हैं? देश जानना चाहता है कि जो निर्णय नोटबंदी का लिया गया है, वह अव्यावहारिक है, परिणाम को बिना समझे हुए किया गया है, तो इस पर बहस हो जाए। हम जनता की आवाज रखेंगे, गरीब की आवाज रखेंगे, गांव की आवाज

रखेंगे, तकलीफ रखने का काम करेंगे। चर्चा से विपक्ष नहीं भागता है, तो सत्ता पक्ष को भी नहीं भागना चाहिए, बहस शुरू होनी चाहिए और उस पर मत विभाजन होना चाहिए।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्षा जी, दो बातें हैं। पहला, खड़गे साहब ने एक दुःखपूर्ण विषय के बारे में यहां अपना विचार व्यक्त किया। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जब वहां बार्डर पर एक्शन चल रहा है, कोम्बिंग आपरेशन चल रहा है, तो हमारे वीर जवानों की शहादत के बारे में, उनको श्रद्धांजलि के बारे में राजनीति करना शोभा नहीं देता है, ठीक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान) वहां एक्शन अभी भी चल रहा है। ...(व्यवधान) कोम्बिंग आपरेशन चल रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई राजनीति नहीं। ठीक है, बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : हमारे वीर जवान लड़ रहे हैं। ...(व्यवधान)

दूसरी बात, ये लोग बहस के बारे में कह रहे हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा कि 16 तारीख से सरकार बहस के लिए तैयार है। ...(व्यवधान) काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो मुहिम हमने शुरू की है, संघर्ष शुरू किया है, उससे आम जनता को, गरीबों को लाभ पहुंचा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई राजनीति नहीं, बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : पूरा देश मोदी सरकार के साथ है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए 16 तारीख से हम तैयार बैठे हैं। हर दिन हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) लेकिन एक पीड़ा की बात है, आपने दूसरे सदन में चर्चा शुरू की। वहां छः घंटे की चर्चा करवाई, बीच-बीच में उसे रोका, लेकिन यहां चर्चा अब तक शुरू नहीं की। ...(व्यवधान) आप चर्चा करिए। ...(व्यवधान) सुदीप बंदोपाध्याय जी ने कहा कि कल से शुरू करेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया?

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, यदि खड़गे साहब और ज्योतिरादित्य जी मानेंगे, तो अब से चर्चा करना शुरू करते हैं, हम अभी से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) हर पहलू के बारे में हम जवाब देंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ? बैठिए। क्या हो गया? बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई राजनीति नहीं।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, खड़गे जी जब चाहें वाक इन करें, जब चाहें वाक आउट करें, इससे संसद का कोई फायदा नहीं होगा। जब चाहे वाक इन करेंगे, जब चाहे वाक आउट करेंगे, हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) इसमें दो अलग आवाजें नहीं हो सकतीं, पार्लियामेंट से दो सुर नहीं निकल सकते। ...(व्यवधान) काले धन के खिलाफ पूरा देश एक है, पूरा सदन एक है, ऐसा हम मानते हैं। ...(व्यवधान) विपक्ष भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। ...(व्यवधान) जब ऐसा है तो इसको वोटिंग के तहत डिवाइड करना, एक डिवाइडेड मैसेज देश को देना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब क्या हुआ?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर मुझे सबको बोलने देना होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसका नाम लिया?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान) हमने आपसे बार-बार यही विनती की है कि किसी भी प्रोविजन में डिबेट शुरू कीजिए, उस पर वोटिंग हो जाए, मतदान हो जाए, हम उसके लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) वे कहते हैं कि हम भाग रहे हैं।...(व्यवधान) हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं।...(व्यवधान) गरीबों का गला घोंटकर,...(व्यवधान) 82 लोग मर गए हैं, लाखों लोग जख्मी हो गए हैं।...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, यदि ये तैयार रहते, तो 16 तारीख से 30 तारीख तक 12 दिन हो गए हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : गरीब लोगों को दो हजार रुपये के लिए लाइन में अपनी जान खोनी पड़ रही है।...(व्यवधान) आप गलत हैं।...(व्यवधान) हम तैयार हैं।...(व्यवधान) हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप सब बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बार-बार इधर से, उधर से कुछ मत बोलिए। खड़गे जी, आपने जो बात कही, मैंने वह सुन ली है कि मैं सब रूल अलग रख सकती हूं, मेरी जो पावर है। मेरा आज सबसे निवेदन है, अगर आप तैयार हैं, तो एक बात हो सकती है। मैंने वैसे भी शून्य काल पर चर्चा घोषित कर दी है। आप सब जानते हैं। जोशी जी ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। हम शून्य से शुरू करेंगे तो ब्रह्मांड तक भी पहुंच जाते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसलिए मैं सब बातें अलग रखती हूं क्योंकि आप नियम 193 के अंतर्गत, नियम 56 आदि किसी रूल के अंतर्गत तैयार नहीं हैं। सब रूल दूर रखकर आप अभी तुरंत चर्चा शुरू कीजिए। हम शून्य से कुछ खोजने की कोशिश करें। मैं अभी तैयार हूं। आप शुरू कीजिए। I am ready.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप चाहें तो बाकी सब बात छोड़कर शून्य में खोजने की कोशिश कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : हम इस चर्चा में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी किसी रूल के अंतर्गत चर्चा के लिए तैयार नहीं है। If you don't want to debate, it is alright.

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: If you want to debate, I am ready.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: We are ready, Madam.… (*Interruptions*) एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सब रूल बाजू में रखकर हो सकता है।

…(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, the whole House can understand your anguish when you say that nobody is prepared – neither from this side nor that side – to go along with the rules. Every Member is

aware of the anguish that you have expressed from the Chair. It is a caution to every Member who is present in this House. My request to you, Madam, is this. When the Parliamentary Affairs Minister has said today that we cannot divide this House on black money, I would like to know who is dividing it. Neither from the Opposition nor the Leader of the Opposition nor leader of the Trinamool Congress Party is saying that we want a `Division' on black money. We are asking a discussion on the predicament that the people of this country are facing relating to demonetization. That is the issue I think the Government should agree to have a discussion. Every State, every citizen of this country is going through hardship. That is the reason why we want to express ourselves. We don't want a `Division' on black money. … (*Interruptions*) On the black money issue, yesterday we have said that the whole country and every political party is one with the Government. We don't want any `Division' on black money. But it is a discussion or a debate……. (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Jaitley *ji,* let him complete. Then, you can speak. I will call you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would also say that our party is not against demonetization. It is the trouble that the citizens of this country are facing everyday is the reason why we want a discussion. … (*Interruptions*)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : अध्यक्ष महोदया, महताब जी ने जनता की परेशानी के विषय में बताया है, सभी चर्चा चाहते हैं ...(व्यवधान) तो इसमें डिवीजन का सवाल ही नहीं है। ...(व्यवधान) सभी चाहते हैं कि परेशानी दूर हो, आप तुरंत महताब जी के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कराएं। ...(व्यवधान)

12.26 hours

(*At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Sunil Kumar Mondal and Shri P.K. Biju and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you want to discuss the issue, you can start it just now.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It shows that you do not want to discuss the issue.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now we take up 'Zero Hour'. Shri Srinivas Kesineni.

… (*Interruptions*)

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Madam Speaker, I would like to raise an issue that is in the hearts and minds of every person of Andhra Pradesh, that is providing legal sanctity for the Special Assistance Package which the hon. Finance Minister had announced on 7th September, 2016. … (*Interruptions*) The Special Category Status had been promised by the then Prime Minister on the floor of Rajya Sabha on the demand of the Opposition leaders at that time and it was also put in the Andhra Pradesh Re-Organisation Act, 2014. … (*Interruptions*) But after the scrapping of the Planning Commission and coming into place of the *Niti Ayog*, the Government is now telling that no State will get the Special Category Status. … (*Interruptions*) After a lot of deliberations and a big exercise, the hon. Finance Minister had announced a Special Assistance Package for Andhra Pradesh. … (*Interruptions*) But I would like to point out that it has been 2 ½ months since the announcement made by the Finance Minister. … (*Interruptions*) No further information has been forthcoming since then. … (*Interruptions*)

Madam Speaker, I would like to ask the Finance Minister, through you, as to the legal status of the Special Assistance Package promised to Andhra Pradesh. … (*Interruptions*) The Central Government must assure the people of Andhra Pradesh that their commitment will remain legally valid throughout the entire period of the package. … (*Interruptions*)

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं डिब्रूगढ़ लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मैं अपनी मातृभाषा असमीया में बोलना चाहता हूं।

[*]Bogapani is an important tea garden in Tinisukia district of Assam. There is a Railway station in Bogapani. But to the utter dismay of Railway passengers travelling to and from Bogapani, the station has remained shut for past several

[*] English translation of the speech originally delivered in Assamese

years for the reason best to the Railway Ministry. The sudden closure of this important Railway station has caused serious inconveniences to the railway commuters of the locality. Moreover, various anti-social elements are also using the abandoned railway properties for their dirty activities. … (*Interruptions*)

I, therefore, urge upon the Railway Ministry to re-open the Bogapani Railway station in the greater interest of the railway commuters. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रामेश्वर तेली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र उदयपुर से अहमदाबाद तक आमान परिवर्तन कार्य की ओर आकृष्ट करता हूँ। इसे शीघ्रता से पूरा कराया जाए। ...(व्यवधान) वर्ष 2016-17 में इसके लिए लगभग सात सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, फिर भी अभी तक उसका काम धीमी गति से ही हो रहा है। ...(व्यवधान) उदयपुर झीलों की नगरी है। उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी में भी लिया गया है। दक्षिण के राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जाने के लिए अगर उदयपुर से अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर ब्रॉडगेज लाइन शीघ्रता से कम्पलीट हो जाती है तो इससे यातायात में सुविधा हो जाएगी। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अहमदाबाद वाया डुंगरपुर, हिम्मत नगर रेल आमान परिवर्तन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मैं सदन के माध्यम से केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी का ध्यान अमेरिकी एजेंसी नासा की चौंकाने वाली रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहती हूं। ...(व्यवधान) नासा ने 8 दिसंबर 2009 से लेकर दिसंबर, 2015 तक भूजल स्तर की स्टडी की है। इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने नासा की सैटेलाइट ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेक्स से इमेज ली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि झुंझुनू, चुरु और सीकर राजस्थान के तीन जिलों का जल स्तर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे तेज गति से घट रहा है। ...(व्यवधान) रिपोर्ट में कहा गया है

भूमिगत जल के दोहन की अगर यही स्थिति रही तो उत्तर भारत के इन तीन जिलों के अलावा हरियाणा और दिल्ली में करीब दस करोड़ आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। पूर्व में सीरिया गिरते जल स्तर के मामले में विश्व में एक नंबर पर था और अब उत्तर भारत के ये क्षेत्र पहले नंबर पर घोषित हो गए हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि नासा की रिपोर्ट पर ध्यान दें और झुंझुनू, चुरु और सीकर क्षेत्रवासियों की मदद यमुना बेसिन के माध्यम से 1994 के समझौते के तहत पीने का पानी उपलब्ध कराकर करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत, श्री सी.पी. जोशी, श्री आलोक संजर, श्री हरीश मीणा, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker, Madam, I want to bring to the notice of the House and the Government that there are about 400 ground handling companies appointed at the Airport, which employ close to three lakh people; and as per the new policy, its para 19 authorizes the airport operators to choose, and only through them, appointments can made… (*Interruptions*) Through those appointments, if the number of companies is restricted, then it would lead to a lot of unemployment amongst the people who are handling the ground handling services. … (*Interruptions*) If the policy authorizes the airlines to do it, then it would be an unwholesome burden on the airlines to deal with the ground handling services. Better option is to allow the airlines to pick up their own ground handling company and, in return, get the handling done by those people. In that view, para 19 needs to be re-looked. Thank you… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुधीर गुप्ता, श्री देवजी एम. पटेल, श्री रोड़मल नागर, श्री आलोक संजर, डॉ0 किरीट पी. सोलंकी, श्री सी.पी. जोशी और श्री अर्जुन लाल मीणा को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.45 hours

12.33 hours

The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past Twelve of the Clock.

12.45 hours

The Lok Sabha re-assembled at Forty Five Minutes past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Sudipji, what is it?

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam Speaker, Ananth Kumar ji said that in Rajya Sabha discussion had started taking place. But what I want to say, राज्य सभा में जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस के ऊपर ही आलोचना शुरू हो गयी। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I do not think so.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The discussion had taken place on the basis of the notice given in Rajya Sabha.… (*Interruptions*) So, naturally, it is not implied to us. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं उसकी चर्चा नहीं शुरू कर रही हूं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have given you one chance कि मैं अब भी शून्य काल में चर्चा कराने के लिए तैयार हूं।

…(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : We want discussion for the interest of the common people. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, I know that. But now, do not disturb other hon. Members. शून्य काल सब मैम्बर्स के लिए है और सबको अपनी-अपनी समस्या कहनी है and that is why I am allowing them.

… (*Interruptions*)

12.46 hours

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में जो भी बोलना चाहते हैं, वे सब आपके कुलीग्स हैं। मैंने कहा है कि I am ready to allow you.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप चाहें, तो हम अभी डिसकशन स्टार्ट कर सकते हैं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour' – Dr. Sunil Gaikwad.

… (*Interruptions*)

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मेरे लोक सभा क्षेत्र लातूर, महाराष्ट्र से टेम्भूरनी तक स्टेट हाईवे है, जो बहुत ही खराब हालत में है। ...(व्यवधान) मैं उसे नैशनल हाईवे में कन्वर्ट करने की मांग करता हूं। ...(व्यवधान) टेम्भूरनी लातूर को नैशनल हाईवे में घोषित करके तुरंत काम शुरू किया जाये। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी से विनती करना चाहता हूं कि मेरे लातूर क्षेत्र के सभी नैशनल हाईवेज का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र को डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Rahul Shewale – not present.

Shri Gajanan Kirtikar.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to raise the matter of pensioners of the private sector banks.

I had sent a representation of All-India Bank Retiring Federation, Indore alongwith demands of pensioners like enhancement of their Family Pension, removal of discrimination in DA among retired persons and holding discussion and meeting with the Federation on a regular basis for the redressal of their grievances immediately on humanitarian grounds.

In view of the prevailing economic situation, the demands of these pensioners are genuine and need to be looked into favourably. As the pension in the bank is payable as per the provision of the Bank Employees Pension Regulation 1995 of the respective bank, therefore, I request the Minister of Finance to take up the issue of retiring fellow and there should be immediate

changes in the pension scheme with the mandate from the bank at the earliest so that the pensioners can be benefitted.

Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Shrirang Appa Barne, Dr. Shrikant Eknath Shinde, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Harishchandra *Alias* Harish Dwivedi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Subhash Patel and Shri Sudheer Gupta are permitted to associate with the issue raised by Shri Gajanan Kirtikar.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय प्राचीन संचार और डाक सेवा के संबंध में रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) भारत सरकार ने पहले भी चाहे डाकघरों में एटीएम लगाना हो या कोर बैंकिंग की सेवा शुरू करनी हो, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय संचार और डाक सेवा के संबंध में किये हैं। ...(व्यवधान) लेकिन आजादी के पहले से जो ग्रामीण डाक सेवक है, जो अंतिम कड़ी में जाकर काम करता है, उस डाक सेवक को अभी भी छः हजार रुपये मिलते हैं। ...(व्यवधान)

पहले जो तलवार कमेटी बनी, उसकी सिफारिशें पूरी तरह मानी नहीं गयीं। अब माननीय न्यायालय ने भी इसे सिविल सर्वेंट माना है। ...(व्यवधान) इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इन डाक सेवकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि वर्षों चली आ रही उनकी मांग की पूर्ति हो सके। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुधीर गुप्ता, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री हरीश मीना, श्री बलभद्र माझी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान किसानों की जीवनदायी महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह योजना कृषकों के लिए वरदान बनकर आई है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not disturb like this. This is not fair.

… (*Interruptions*)

श्री रामदास सी. तडस : अध्यक्ष महोदया, इसको सफलता के धरातल पर लाने हेतु अत्यधिक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।...(व्यवधान) अभी जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से इसका प्रसार किया जा रहा है, किन्तु इस योजना के प्रचार के लिए ग्रामीण स्तर पर कैम्प, प्रभातफेरी आदि का आयोजन करने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Saumitra Khan, do not do that. वे भी आपके कॅलीग हैं, वे भी अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। Please do not do that.

… (*Interruptions*)

श्री रामदास सी. तडस : अध्यक्ष महोदया, विज्ञापन एवं प्रादेशिक भाषा के माध्यम से प्रचार करने से किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी मिल पाएगी, जिससे किसान इस योजना का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाएंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस तरह आवाज करना अच्छी बात नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री रामदास सी. तडस : फलस्वरूप किसानों की आत्महत्या को रोक पाने में सरकार को सफलता मिल पाएगी। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी को श्री रामदास सी. तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab – Not present.

Shri P.K. Biju – Not present.

Shri Rajeev Satav – Not present.

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 19 कस्तूरबा गांधी विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। ...(व्यवधान) इन विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति एवं बेड-किट की बहुत बड़ी समस्या है, जिनसे छात्राओं की शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ता है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि स्वीकृत विद्यालयों में 41,000 रुपये का एस्टीमेट विद्युत कनेक्शन हेतु बिल्डिंग निर्माण के साथ स्वीकृत किया गया था। ...(व्यवधान) कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें विद्युत कनेक्शन के लिए 2,40,000 रुपये लागत का एस्टीमेट आ रहा है। इस कारण विद्यालयों में स्थानीय प्रशासन द्वारा विद्युत कनेक्शन करा पाना संभव नहीं है। ...(व्यवधान) साथ ही, विद्यालयों में खाद्यान्न सामग्री बहुत घटिया किस्म की दी जाती है। ...(व्यवधान) यह समस्या प्रदेश के लगभग प्रत्येक जनपद के विद्यालयों की है।...(व्यवधान) मैं यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बच्चों के लिए 750 रुपये प्रति बच्चा बेड किट के लिए मिलते हैं, जो बहुत कम है। इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रदेश के स्थापित विद्यालयों के खाद्यान्न एवं बेड किट की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा बच्चों के भविष्य को देखते हुए री-एस्टीमेट की मांग करते हुए, उसके आधार पर धन उपलब्ध कराकर, जनहित की इस समस्या का निस्तारण कराएं।...(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुभाष पटेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी एवं श्री शरद त्रिपाठी को डॉ. अंशुल वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं पश्चिमी चम्पारण से बिलाँग करता हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर है, जो गांधी जी की कर्मभूमि रही है।...(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र में दो ब्लॉक ऐसे हैं, जिनकी कुछ पंचायतों की भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते, वहां विद्युतीकरण नहीं हो सकता है, जैसे रामनगर विधान सभा के, रामनगर ब्लॉक के बनकटवा-करमहिया और नौरंगिया गांव, वाल्मीकि नगर विधान सभा के ठकराहां

ब्लॉक के मोतीपुर, ठकराहां, कोइरीपट्टी, धुमनगर, हरपुर-श्रीनगर, भवानीपुर-जगराहां आदि ऐसे गांव हैं, जहां विद्युतीकरण नहीं हो सकता है।...(व्यवधान) ये गांव नदी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं।...(व्यवधान) वहां सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर विद्युतीकरण किया जाए, अन्यथा सौर ऊर्जा देने से भी काम चलने वाला नहीं है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस काम को पूरा कराया जाए। यह अति महत्वपूर्ण कार्य है।...(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena – Not present.

श्री राजन विचारे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला नवी मुंबई एक ऐसा शहर है, जो कई शहरों और जिलों को जोड़ता है। ...(व्यवधान) इसके कारण वहां अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। ...(व्यवधान) साथ ही साथ यहां पर ठाणे, कल्याण, अम्बरनाथ और बदलापुर सहित आस-पास के अन्य शहरों का विकास भी तेजी से हो रहा है।...(व्यवधान) नवी मुंबई के विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन तीस से पैंतीस हजार लोग नौकरी एवं व्यवसाय के लिए आना-जाना करते हैं। ऐसी सड़कें वाहनों के लिए छोटी पड़ रही हैं। ...(व्यवधान) साथ ही यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनने जा रहा है। ...(व्यवधान) इस हवाई अड्डे के तैयार होने के बाद यहां पर वाहनों की संख्या में और भी वृद्धि हो जाएगी।...(व्यवधान) इसलिए शहर के बढ़ते यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए अभी से ही कोस्टल रोड का निर्माण करना आवश्यक है।

नवी मुंबई महानगर पालिका ने बेलापुर से वाशी का करीब 10.5 किलोमीटर लम्बाई का एवं वाशी से ठाणे 16.5 किलोमीटर लम्बाई वाला 8 लेन का खाड़ी के किनारे दो चरणों में मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है,...(व्यवधान) जिसे मई 2014 को कोस्टल जोन मेनैजमेंट के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है एवं इसके लिए करीब 5038 करोड़ रु. की निधि आवश्यक है।...(व्यवधान) इतनी बड़ी रकम नवी मुंबई महानगर पालिका खर्च नहीं कर सकती। इसलिए इस संदर्भ में एम.एम.आर.डी.ए. परियोजना के लिए पूरी निधि देने में असमर्थ है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार एम.एम.आर.डी.ए. एवं सड़कों के सहयोग से इस जरूरी परियोजना को पूरा करने में मदद करे। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुभाष पटेल और श्री अरविंद सावंत को श्री राजन विचारे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश बिधूड़ी - अनुपस्थित।

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रकृति द्वारा उपलब्ध जल को लेकर कई राज्यों में बंटवारे को लेकर यह विवाद का विषय बना हुआ है।...(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अन्य राज्यों के सामने हाथ फैलाकर, पानी मांगने के स्थान पर, अपने राज्यों में उपलब्ध जल के सही नियोजन को उपयोग करने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना बनाकर राजस्थान राज्य को जल के संदर्भ में एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने का संकल्प लिया है।...(व्यवधान) इस संकल्प की हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ...(व्यवधान) इस योजना के प्रथम फेज में तीन हजार गांवों का चयन किया गया है।...(व्यवधान) एवं वहां पर योजनाबद्ध तरीके से पानी का सही नियोजन करके, जहां राजस्थान में पूर्व में सिर्फ 25 ब्लॉक सेफ जोन में थे, बाकी पूरा राज्य डार्क जोन में आता था, अब मुख्य मंत्री जी की इस जल स्वावलम्बी योजना के क्रियान्वयन के कारण जो 50 ब्लॉक हैं, वे सेफ जोन में आ गये हैं।...(व्यवधान) बढ़े हुए पानी का लाभ करीब 41 लाख लोगों को व 45 लाख पशु धन को मिला है। ...(व्यवधान)

इस योजना का द्वितीय चरण, जो 9 दिसम्बर को प्रारम्भ हो रहा है, आगामी तीन वर्षों में 6-6 हजार गांवों का चयन कर, वॉटर एंड सॉयल कंजर्वेशन का लक्ष्य रखा गया है।...(व्यवधान) चार वर्षों में राज्य के 21000 गांवों तक इस योजना को पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। राज्य की सीमित आर्थिक उपलब्धता के होते हुए भी, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जनता से आह्वान करके, धन एकत्रित कर, जल के संबंध में राज्य को स्वावलम्बी बनाने का प्रथम चरण सफलता पूर्वक पूर्ण किया है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण योजना को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान करने का निर्णय करें। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम.पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री सुभाष पटेल को श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.58 hours

MATTERS UNDER RULE 377—LAID*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members may personally handover the text of the matter as per practice.

… (*Interruptions*)

* Treated as Laid on the Table

(i) Need to regularise the services of Aanganwadi workers as Group 'D' employees and also give them adequate wages and allowances and social security benefits as applicable to Group 'D' employees.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : वर्ष 1975 में भारत सरकार ने समेकित बाल विकास निधि (आई.सी.डी.एस.) योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पोषणीय एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने के मामलों की संख्या में कमी लाना आदि प्रमुख हैं। इस योजना के अंतर्गत समेकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो कि पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रैफरल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख काम करने वाले लोगों में एक हैं-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के कार्यों की सूची बहुत लम्बी है। इनके प्रमुख कार्य हैं- सभी 6 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, सभी गर्भवती माताओं के लिए टीकाकरण, बच्चों के लिए पूरक पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिलाओं का चेक-अप करवाना, गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व एवं बाद की देखभाल करना, नवजात शिशुओं की देखभाल, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व गतिविधियों को व्यवस्थित करने के साथ आंगनबाड़ी का संचालन करना। 1000 लोगों की आबादी पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है। वर्तमान में तेरह लाख से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र देश में चल रहे हैं और इन केन्द्रों पर लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देश की कुपोषण, भुखमरी, उच्च शिशु मृत्यु दर, स्वच्छता की कमी, बीमारियां, शिक्षा का अभाव आदि समस्याओं के निदान के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आई.सी.डी.एस. दुनिया की सबसे बड़े बाल देखभाल कार्यक्रमों में से एक है।

आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा बहुत ही कम मानदेय पर काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी नहीं माना गया है और न ही सरकारी कर्मचारियों की भाँति वेतन, भत्ता एवं अन्य लाभ दिया जाता है। इन्हें पेंशन, चिकित्सा सुविधा, अनुकम्पा नियुक्तियाँ, महंगाई भत्ता आदि कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। संसद में लोकसभा की महिला सशक्तिकरण समिति ने पन्द्रहवीं लोकसभा में 8वीं रिपोर्ट, अगस्त 2011 में "आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्य स्थिति " विषय के साथ रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कुल सोलह सिफारिशें सरकार से की गई थी, परंतु अभी तक सभी सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं।

अतः मेरी भारत सरकार से माँग है कि आँगनबाड़ी कर्मचारियों को कम-से-कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानकर इसके अनुरूप मूल वेतन, भत्ता, चिकित्सा सुविधा, पेंशन एवं अन्य लाभ आदि प्रदान किए जाएं। साथ ही सरकार संसदीय समिति 8वीं रिपोर्ट अगस्त, 2011 की शेष बची सिफारिशों को लागू करे।

(ii) Need to check the industrial waste and pollution caused by industrial factories in Ujjain Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : मेरे संसदीय क्षेत्र में ग्रेसिम उद्योग ग्रुप में 17.11.2016 को दुर्घटना हुई जिसमें फैक्ट्री के मजदूर की मृत्यु जहरीले धुँए से हुई साथ ही इससे 10 मजदूर और भी प्रभावित हुए। ग्रेसिम उद्योग ग्रुप से निकल रहे मलबे से असहनीय दुर्गंध व प्रदूषण जन-जीवन के लिए हानिकारक होता जा रहा है। उक्त मलबा रासायनिक है। इसका सही तरीके से निपटारा न होने से यह स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण के लिए भी खतरा है। कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारी अनेक प्रकार के त्वचा संबंधी रोग, हृदय संबंधी बीमारियों व कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हैं। प्रत्येक माह इस फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में से एक की मृत्यु इन रोगों से होती है। इतना ही नहीं इस फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा का भी ध्यान न रखने के कारण आये दिन श्रमिकों की दुर्घटनाओं में मृत्यु होती रहती है। इससे उत्पन्न प्रदूषण से उज्जैन जिले में क्षिप्रा तथा चंबल नदी प्रदूषित है। चंबल नदी पर ही आश्रित यह इकाई इसी नदी में अपना प्रदूषित जल बहा रही है। प्रदूषण के चलते चंबल नदी न केवल उज्जैन बल्कि मुरैना व भिंड जिलों को भी प्रदूषित कर रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि रसायन, पर्यावरण एवं श्रम मंत्रालयों की एक संयुक्त जाँच समिति गठित कर इसकी उचित जाँच करवायी जाये तथा दोषियों को उचित दंड दिया जाये।

(iii) Need to impress upon Government of Uttar Pradesh to enhance the rate of sugarcane and also ensure payment of arrears of sugarcane by sugar mills to farmers in Uttar Pradesh

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। न तो गन्ने का मूल्य संतोषजनक रूप से बढ़ाया गया और न पिछले बकाए का ब्याज सहित भुगतान हो रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से यह मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के हो रहे इस शोषण को केन्द्र सरकार गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करे कि प्रदेश सरकार गन्ने की कीमत पर पुनः विचार करे एवं चीनी मिलों द्वारा किसानों को पिछले बकाए को ब्याज सहित भुगतान दिलाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाएँ।

(iv) Need to open a railway station in Ridhpur at Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मैं रेलमंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा की समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूँ कि नरखेड-अमरावती रेलवे लाईन पर पड़ने वाले रिद्धपुर में रेलवे स्टेशन की मांग काफी समय से की जा रही है। श्री क्षेत्र रिद्धपुर को महानुभाव पंथ की काशी कहा जाता है। रिद्धपुर में स्थित महानुभाव पंथ के तकरीबन 800 मंदिर हैं और यहां पर देश-विदेश से हज़ारों दर्शनार्थी आते हैं। श्री रिद्धपुर क्षेत्र को तीर्थ स्थल का " ब " दर्जा प्राप्त है, और श्री क्षेत्र रिद्धपुर को पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है। रिद्धपुर महत्वपूर्ण स्थान अमरावती-नरखेड मार्ग पर आते हुए भी यहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है। रिद्धपुर में रेलवे स्टेशन होने से 15 से 20 गांवों को इससे फायदा होगा।

अतः जनहित हेतु जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए श्री क्षेत्र रिद्धपुर में रेलवे स्टेशन बनवाने हेतु उचित कदम उठाकर शीघ्र संबंधित अधिकारी वर्ग को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे कि समस्या का समाधान हो सके।

(v) Need to ensure timely payment of pension and gratuity to retired employees of Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, Jharkhand

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : मेरे लोकसभा क्षेत्र राँची के धुर्वा स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपारेशन लिमिटेड (एच.ई.सी.एल.) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी, पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्तों का भुगतान कई वर्षों से लंबित है। सरकार को सूचित करना चाहता हूँ कि एच.ई.सी.एल. के 1 जनवरी, 1997 से सितम्बर 2008 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, उनको अभी तक ग्रेच्युटी, पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है। एच.ई.सी.एल. भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है। एक समय यह एशिया का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था परन्तु क्रयशक्ति न रहने से यह सार्वजनिक उपक्रम अपनी क्षमता के अनुपात में उत्पादन नहीं कर पा रहा है। बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना ईलाज नहीं करा पा रहे हैं। बहुत ऐसे सेवानिवृत्त कर्मी हैं, जिनका धन के अभाव में समुचित इलाज नहीं होने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। एच.ई.सी.एल. के प्रबंधन और एच.ई.सी.एल. सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के बीच जो ग्रेच्युटी, पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्तों के भुगतान के संबंध में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। अब तक एच.ई.सी.एल. के जितने सी.एम.डी. आए सभी ने ग्रेच्युटी, पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्ता राशि को देने की बात कही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि एच.ई.सी.एल. कम्पनी, धुर्वा, राँची के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उपरोक्त वर्णित ग्रेच्युटी, वेतन पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्तों के भुगतान आदि बकाया राशि यथाशीघ्र दिलवाने की कृपा करेंगे। बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाएगा तो लोगों को आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

(vi) Need to accord environmental clearance to Uranium Corporation of India Limited mines at Jaduguda, Jharkhand

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (झारखण्ड) का जादूगोड़ा, आदिवासी बाहुल्य गरीब एवं उग्रवाद प्रभावित अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.) की जादूगोड़ा खान वर्ष 1967 से चालू की गई थी, जो कि विगत 7 सितम्बर, 2014 से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वनीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण वहाँ का आम जन-जीवन काफी प्रभावित है। वहाँ के लोगों के समक्ष बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मैंने माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से मिलकर उन्हें समस्या से अवगत कराया है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं माननीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उपर्युक्त विषयक को देखते हुए अविलम्ब बंद पड़े यू.सी.आई.एल. के जादूगोड़ा खान को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वनीय स्वीकृति दिलाने की कृपा की जाये।

(vii) Need to develop necessary mechanism to enable people migrated to other States to exercise their right to vote during elections

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार लगभग 3 करोड़ व्यक्ति रोज़गार की तलाश में अपना घर छोड़कर देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। चुनाव के समय ये लोग सामान्यतः अपने घरों से दूर रहते हैं तथा किसी समुचित व्यवस्था के अभाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि लगभग 3 करोड़ की इस बड़ी प्रवासी जनसंख्या के लिए डाक मत पत्रों की अथवा अन्य कोई ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि चुनावों में ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

(viii) Need to reintroduce free Monthly Season Ticket to students for rail journey

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि रेलवे विभाग द्वारा ग्रामीण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए "0 " बैलेंस पर निशुल्क मासिक पास (एम.एस.टी.) बनाया जाता था। लेकिन 2015-16 में रेलवे द्वारा यह व्यवस्था पूर्णतया बन्द कर दी गई है। जिससे ग्रामीण छात्र/छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण अधिक संख्या में गरीब एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. छात्र शहरों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूँ कि रेलवे विभाग द्वारा शिक्षार्थियों को जो पास (एम.एस.टी.) "0 " बैलेंस पर पास बनाया जाता था, उसको दोबारा शुरू किया जाये ताकि ग्रामीण बालक/बालिकाएं शहरों में उच्चतर महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ सकें।

(ix) Need for development and operation of Vadiya Devli Railway station in Amreli Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : गुजरात के अमरेली जिले और राजकोट जिले के मध्य में जेतलसर-ढासा रेल लाइन के ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट जिसकी लंबाई 80 कि.मी. है, की निविदा निकलने के पश्चात् कार्य शुरू किया जा चुका है। पूर्व में यह लाइन मीटर गेज में थी जिसे ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है।

वडिया देवली जो एक तहसील है, इस स्थान पर पहले रेलवे स्टेशन था जिसका संचालन रेलवे विभाग ने किसी कारण से बंद कर रखा है। इस निविदा में वडिया देवली तहसील वाले स्टेशन को शामिल नहीं किया गया है। इस 80 कि.मी. की लाइन में 8 स्टॉपेज है, जिसमें 2 तहसील आती हैं। अतः इस वडिया देवली (तहसील) स्टेशन के पुनर्निर्माण को इस निविदा में शामिल किया जाए। इस बात के लिए मैंने संबंधित ठेकेदार से सम्पर्क किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि इस स्टेशन को निविदा में शामिल नहीं किया गया है। इस स्टेशन को निविदा में शामिल नहीं किए जाने से मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा तथा मेरे द्वारा किए गए अनेक प्रयास भी व्यर्थ हो जाएंगे।

अतः मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि मेरी जनता के साथ प्रतिबद्धता को देखते हुए टेंडर में वडिया देवली तहसील वाले स्टेशन को पुनः संचालित करने के पश्चात यहां रेल के आवागमन के साथ-साथ स्टॉपेज की व्यवस्था की जाए जिससे मेरे क्षेत्रवासियों को सुविधा मिल सके।

(x) Need to enhance the Minimum Statutory Price of Moong Dal (Green Gram) in Nagaur, Merta and Degana in Rajasthan

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के नागौर जिले में और मेरे संसदीय क्षेत्र के मेड़ता एवं डेगाना विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मूंग की फसल का समर्थन मूल्य पर सरकार की ओर से खरीद करने का निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान की है। इस निर्णय से माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय में वृद्धि करने का संकल्प परिलक्षित होता है।

मैं मूंग की सरकारी खरीद में आने वाली कुछ परेशानियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो निम्न प्रकार हैः-

1. समर्थन मूल्य जो कि 5250 रू. है, में वृद्धि की अपेक्षा है।
2. मूंग को तुलवाने के कांटों की संख्या में वृद्धि हो ताकि किसान समय पर अपना माल तुलवाकर बिक्री कर सके।
3. मूंग के उत्पादन में प्रकृति के कारण किस्म में न्यूनता आई है उसे भी या तो सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे अथवा अनुदान के माध्यम से किसान को क्षतिपूर्ति प्रदान कराने का निर्णय ले।

मेरा आग्रह है कि उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर किसानों को राहत प्रदान करने का निर्णय ले ताकि किसान अपने उत्पाद को सुविधाजनक तरीके से बिक्री कर सके एवं अपने माल का सही दाम प्राप्त कर राहत प्राप्त कर सकें।

(xi) Need to formulate a fair and transparent system under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to ensure meticulous execution of the scheme

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों, समस्याओं और विसंगतियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

प्रधानमंत्री जी के सपनों की यह महत्वाकांक्षी योजना कई अर्थों में सचमुच क्रांतिकारी है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी ने न केवल सुदूर गांव के निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वस्थ, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन दशायें मुहैया कराने का संकल्प लिया है, वही दूसरे के लिए कुछ त्यागने की शाश्वत भारतीय परम्परा को भी पुनर्जीवित किया है। उनकी एक अपील पर करोड़ों उपभोक्ताओं द्वारा गैस सब्सिडी का परित्याग बेमिसाल है लेकिन छूट के इन कनैक्शनों को निर्धन परिवारों को पहुंचाना काफी चुनौतीपूर्ण है। सरकार ने अपनी तरफ से अति निर्धन परिवारों को मानक बनाकर उनकी रसोई तक कुकिंग गैस सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि चार से पांच हजार तक की आबादी वाले गांव, जहां बी.पी.एल. परिवारों की संख्या भी अच्छी खासी है, महस दस-बीस परिवारों को ही लाभार्थी सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। इससे कई तरह की विसंगतियों, विद्वेष और बैर-भाव पैदा हो रहे हैं। कई स्थानों पर कानून व्यवस्था की चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। इन विसंगतियों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्र के गैस वितरको नें कमाई के गोरखधंधे शुरू कर दिए हैं। इनकी करतूतों से इस परियोजना के नकारात्मक प्रभाव भी जहां-तहां दिखाई पड़ रहे हैं। गैस वितरकों द्वारा सूची में सम्मिलित लाभार्थियों तक से पैसों की वसूली की जा रही है, जो कि कतई न्यायोचित नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उज्ज्वला नाम के अनुरूप इस योजना के क्रियान्वयन की ओर व्यापक एवं पारदर्शी प्रक्रिया लागू की जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।

(xii) Need to formulate a scheme for development of agriculture-based industry, dairy, horticulture sector and small scale industries in Banswara Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा) : मैं सरकार का ध्यान बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के बाहुल्य के बावजूद अत्यधिक गरीबी है। यहाँ अधिकतर लोगों के पास स्थायी सम्पत्ति नहीं है तथा लोग अत्यंत गरीबी में जीवन-यापन कर रहे हैं। क्षेत्र में किसी भी तरह का उद्योग नहीं है तथा कृषि उत्पादों की स्थिति भी निराशाजनक है।

मेरा माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री से अनुरोध है कि क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी, बागवानी को स्थापित करने हेतु विशेष योजना का सृजन करें। माननीय उद्योग मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर इस क्षेत्र में उद्योग स्थापना में सहायता करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त सरकार इस क्षेत्र के संसाधनों पर आधारित अन्य योजना क्रियान्वित करने की रणनीति बनाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों के जन-जीवन के स्तर को सुधारा जा सके एवं समावेशी आर्थिक विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारा जा सके।

(xiii) Regarding drought situation prevailing in Karnataka

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Karnataka is having drought for a third year and apparently its worst in about four decades. Farmers missed sowing during both the kharif and rabi seasons. Out of 176 taluks, 139 have been declared drought-hit, leading to migration of thousands to cities. Only the coastal districts have escaped the water problem. The rain fall in the state is 31 per cent less than normal. The total estimated loss due to drought in the state is Rs. 17,193 crore and Government of Karnataka has submitted a memorandum seeking central assistance of Rs. 4,702.54 crore for drought mitigation measures in Karnataka during Kharif 2016. Therefore, I request to the Union Government to give immediate attention to this matter and take necessary steps to release the money at the earliest.

(xiv) Need to sanction additional funds for construction of fishing harbours at Arthungal and Thottappally in Alappuzha district, Kerala

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): The construction activities of two major fishing harbours, Arthungal and Thottappally in Alappuzha district has to be finished immediately. For the construction activities of Arthungal fishing harbour the Central Government has already sanctioned Rs. 49.39 crore but it has been estimated that an additional amount of Rs. 61.57 crore has to be sanctioned considering the coastal settings at the site. Thottappally fishing harbour was inaugurated in 2011 and due to siltation it has not been functioning. It is recommended to sanction Rs. 77.72 crore for the maintenance activities at the site.

(xv) Regarding problems faced by farmers of Tamil Nadu due to demonetisation of currency notes

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): The problems faced by farmers due to demonetisation and the Reserve Bank of India's restrictions on cooperative banks & societies had hit very badly the agricultural operations in Tamil Nadu. The people in rural areas, mostly farmers and agro workers, bank with 4474 Primary Agricultural Cooperative Credit Societies (PACC) for their time-bound agricultural activities.

Therefore, the Government of Tamil Nadu has rolled out a special package for farmers through cooperative institutions to mitigate the hardships faced by them due to demonetisation. The success of special package would depend solely on availability of adequate currency notes with cooperative institutions.

MPs from our party have requested the Finance Minister for immediate release of Rs. 3000 crore in currency notes for crop loans in Tamil Nadu during November-December, the peak agricultural season. This should be in addition to the regular flow of currency notes at par with scheduled commercial banks. The PACCs should be allowed to accept repayment of loans by cash (including old Rs 500 and 1,000 notes). The District Central Cooperative Banks should be permitted to disburse money to PACCs without Rs. 24,000 cap per week to support agricultural operations with immediate effect.

I urge the Union Government to take a serious note on the plight of farmers in Tamil Nadu and take necessary steps in this regard.

(xvi) Need to set up food park and Agri-Export Zone in Theni district of Tamil Nadu

SHRI R. PARTHIPAN (THENI): Theni District in Tamil Nadu is famous for the produce of mango, grapes, banana and spices. There is also a great potential for organic farming in Theni and Usilampatti region. Though there has been an action plan to ensure forward and backward linkage by adopting cluster approach under the National Horticulture Mission, there has not been any active support from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. I request the Government to aid/support in setting up of Agri-Export Zone (AEZ) for production and cold-storage facilities for fruits such as mango, grapes etc.

The Government should also set up a Horticulture Institute at Usilampatti. Post Harvest Management facilities should also be set up for various fruits and vegetables in Theni district as part of the National Horticulture Mission.

Farmers have already organised themselves into grape growers Association, Mango Growers Federation etc. to take up organised cultivation and marketing of the produce. There is also great potential for processing of chilli, coriander, and tamarind, etc.

I, therefore, humbly urge the Government of India to set up linkage such as cold storage facilities, Food Park and Agri-Export Zones in this region for promotion of fruits and vegetables.

(xvii) Need to provide medicines to poor at affordable prices

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Prices of medical drugs are sky rocketing. There seems to be no relief to the poor, who cannot afford them to save their lives. There is a need for intervention by the Government to bring down prices of essential drugs and make them affordable to poor and needy. Health infrastructure needs to be modernised and small and medium health centres across the country be set up with sufficient storage of medicines. This is the most essential of all other important things to be done by the Government. I would like to urge the hon. Minister to look into the aspect of providing affordable medicines to the poor and ensure that medicines are available at affordable prices.

(xviii) Regarding timely execution of renovation and conservation of Gadakkhai Heritage Project in Cuttack, Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Cuttack Municipal Corporation (CMC) has requested the Archaeological Survey of India time and again for early execution of work pertaining to the renovation and conservation of Gadakhai Heritage Project under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) Programme of Cuttack City. However, the ASI has not taken any action on the requests of the Cuttack Municipal Corporation (CMC) so far. The CMC cannot take up the work of beautification, development of infrastructure and illumination till the ASI completes the work of renovation and conservation of Moat wall. I, therefore, urge the Government to impress upon the ASI to take immediate necessary steps for timely execution of the said project.

(xix) Need to enhance the rate of pension under Employees Pension Scheme, 1995

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : देश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुरक्षा के साथ उनके वृद्धावस्था जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को लागू किया गया है। वर्तमान समय में यह पेंशन स्कीम राज्यों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इस योजना के विरोध में विगत वर्ष में जंतर-मंतर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सहकारी संगठन इत्यादि के सेवानिवृत्त कर्मचारी विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के विरोध में जन आंदोलन कर रहे हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद मात्र 300 से 500 रूपए का पेंशन मिलता है जो आज की महंगाई में बहुत ही कम है जो देश में वृद्धावस्था के अंतर्गत दी जा रही धनराशि से भी बहुत कम है। देश के केन्द्रीय कर्मचारियों को हर वेतन आयोग में बढ़ोतरी से उनकी पेंशन में बढ़ावा मिलता है। आज उनको 15 हजार से 50 हजार तक पेंशन मिल रही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 को 21 वर्ष पूर्व लागू किया गया था, लेकिन आज के माहौल में कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 का रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कोई महत्व नहीं है क्योंकि 20 साल की सेवा के बाद केवल 500 रूपए मिल रहा है। वर्तमान माहौल में इसमें रिटायर्ड राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन में बदलाव किया जाना आवश्यक है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सहकारी संगठन इत्यादि के सेवानिवृत्त कर्मचारी को कम से कम 5000 रूपए की पेंशन प्रतिमाह की जाये एवं कर्मचारी पेंशन योजना-1995 में इस हेतु समुचित संशोधन किया जाये।

(xx) Need to establish a cluster-cum-handloom park at Mangalagiri in Andhra Pradesh

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Mangalagiri is world famous for handloom products especially cotton sarees, and these exquisite sarees are having huge demand globally. Nearly 4,000 weavers are depending on weaving on self-owned 1,000 looms and 2,800 hired looms. Out of these 4,000 weavers, about 2,000 are enrolled under co-operative fold and others are still outside co-operative fold. Secondly, about 40% of people from Mangalagiri are dependent on handloom weaving and allied industry i.e., yard dealers, traders, wrappers, dyers etc. Thus, around 4,000 looms and 10,000 people are directly or indirectly dependant on the industry for their livelihood.

There is no problem as far as raw material is concerned since Guntur district is a large cotton growing area in Andhra Pradesh and there are about 80 spinning mills around it.

Unfortunately, these skilled weavers are committing suicides as they are not having required infrastructural facilities, proper guidance from experts and marketing facilities. Their problem aggravates during monsoon as water enters pits and looms are immobilized and thus their work is affected.

Mangalagiri has close proximity to NH 5, Vijayawada and Guntur. If handloom park is established, it would attract weaving and garment industries which, in turn, bring in customs, containers, banking and quality control facilities under one roof.

In view of the above, I request Government of India to kindly consider setting up of Cluster-cum-Handloorn Park at Mangalagiri with processing and other units which will not only push the world famous Mangalagiri cotton sarees but also help in providing gainful employment to thousands of youth and to keep the tradition alive.

(xxi) Regarding pending projects under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I wish to bring to your kind notice the functioning of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in my constituency, Araku as well as in the Visakhapatnam District of Andhra Pradesh.

As the chairman of the DISHA committee of Visakhapatnam district, I have been conducting meetings at the district level as it has come to the notice that Visakhapatnam has not been allocated works under PMGSY since 2013. Many works to the tune of Rs. 230 crore are left unfinished due to non-performance of the contractors or no-response to tenders.

Due to these factors, further works are being affected and hence the connectivity issue is being stalled. Hence, I request the Ministry of Rural Development through you, that such works which are held up due to non-performance should be immediately given to others on supplementation basis and also action be initiated against such contractors who have defaulted.

Further, I also request the Ministry to issue necessary instructions to the district authorities to take measures in resolving the pending projects, so that fresh approvals are accorded.

(xxii) Need to address the problems of farmers in the country

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : आज देश भर में किसानों की क्या दुर्दशा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान जो देश का अन्नदाता है, वही भूखा और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर है। किसान खुद तो भूखा सो जाता है, पर दूसरे का पेट भरने की चिन्ता उसे हमेशा सताती है। सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि हमारे किसानों की समस्याओं का समुचित हल करे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर तो हो गए हैं, लेकिन किसान दिनों-दिन गरीब होता जा रहा है। यह एक विचारणीय प्रश्न है।

देश में 68 फीसदी खेती वर्षा पर निर्भर है और वर्षा कम व ज्यादा होने पर इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। बिचौलिए और साहूकारों के कर्ज के बोझ से किसान हमेशा दबा रहता है। देश के किसी बड़े भाग में बाढ़ आ जाती है, तो काफी बड़ा भू-भाग सूखे की चपेट मे रहता है। प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। समय से खाद और बीज नहीं मिलता है। उत्तम किस्म के बीजों का अभाव व उसका इतना अधिक मूल्य होता है कि किसान उसे खरीद नहीं पाते हैं। कीटनाशक दवाईयाँ भी अत्यधिक महंगी हो चुकी हैं। फसल बीमा योजना किसानों को किसी भी तरह से मदद करने में अपनी भूमिका साबित करने में असफल हो चुकी है। किसानों के फल और सब्जियों का रख-रखाव और समुचित मूल्य नहीं मिलता है। फसल पैदा होने पर खरीदार नहीं होते, जिससे बिचौलिए को मजबूरन कम दामों पर बेचना पड़ता है। जब किसानों के उत्पाद उनके हाथों से निकल जाता है, तो बाजार में रेट दोगुना हो जाता है। यह कैसा विडम्बना है।

मैं समझता हूं कि किसानों के बारे में किसी न किसी विषय पर प्रत्येक सत्र में चर्चा जरूर होती है। माननीय सदस्यगण, किसानों की समस्या के बारे में सरकार के सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं, किन्तु सरकार उस पर यथोचित रूप से अमल नहीं करती है। जिसका परिणाम है कि आज देशभर के किसान आत्म हत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में तकरीबन 21 हजार किसानों ने आत्म हत्या की है और वर्ष 2015 में यह आकड़ा बढ़ने वाला ही होगा। यह कितनी शर्मनाक बात है कि हम देश के अन्नदाता को खुशहाल जीवन देने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर पाए हैं।

(xxiii) Need to control Sepsis, a life threatening disease

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): The attention of the Government may be drawn to the emerging medical threat of increased deaths due to Sepsis. Sepsis is a life-threatening condition that arises when the chemicals are released into the blood to fight infection trigger widespread inflammation causing eventual organ damage and death.

A nationwide study in 2012 found a prevalence of sepsis within ICUs of hospitals: one in four patients admitted in ICUs contracted the ailment in emergency department of hospitals. Almost one in two patients with sepsis died. 859 (4209 surveyed) or 27.6% of the patients who died of sepsis were not operated upon and were in hospital for non-surgical treatment.

In the U.S., sepsis accounts for far more deaths than the number of deaths from prostate cancer, breast cancer and AIDS combined. This has been declared as a leading cause of death in developed nations like the United States and United Kingdom.

The reasons for the rising incidence could be poor hospital hygiene, abuse of antibiotics or rampant self-medication among people. I, therefore, urge the government to take immediate steps to sensitize the masses on the subject of sepsis and undertake studies to estimate the impact of the medical condition. Continued surveillance, effective infection control programmes, rational use of antibiotics and enhanced public awareness can reduce the incidence of sepsis and hospital-acquired infections, improve patient care and help better prioritization of resources.

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You do not want to discuss anything.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow the 1st December, 2016 at 1100 a.m.

12.59 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 1, 2016/Agrahayana 10, 1938 (Saka).